भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. 160*
13 फरवरी, 2026 को उत्तर देने के लिए

बिहार में मेगा फूड पार्क और प्रसंस्करण अवसंरचना

***160 # श्री शंभू शरण पटेलः**

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश, विशेष रूप से बिहार में, परिचालन में आए मेगा फूड पार्कों और कृषि-प्रसंस्करण समूहों (क्लस्टरों) की संख्या कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन पार्कों में कितनी प्रसंस्करण इकाइयों ने उत्पादन शुरू किया है;

(ग) क्या महत्वपूर्ण अवसंरचना या साझा सुविधाओं में विलंब के कारण बिहार सहित इन पार्कों के उपयोग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) कम उपयोग हो रहे पार्कों में निजी निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(च) इन सुविधाओं के माध्यम से, विशेष रूप से बिहार में, अब तक रोजगार के कितने अवसर सृजित हुए हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
(श्री चिराग पासवान)

(क) से (च): विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

*****

दिनांक 13 फरवरी, 2026 को उत्तर हेतु " बिहार में मेगा फूड पार्क और प्रसंस्करण अवसंरचना" के संबंध में राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या * 160* के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफ़पीआई) मेगा फ़ूड पार्क (एमएफपी) योजना और कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर (एपीसी) योजना को कार्यान्वित कर रहा है, जो केन्द्रीय क्षेत्र अम्ब्रेला योजना "प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई)" की घटक योजनाएं हैं। एमएफ़पी और एपीसी योजना का मुख्य उद्देश्य फार्म से बाज़ार तक मूल्य श्रृंखला के साथ खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए आधुनिक अवसंरचना का निर्माण करना है। जबकि एपीसी योजना को 15 वें वित्त आयोग चक्र के दौरान जारी रखा गया था, एमएफपी योजना को 01.04.2021 से बंद कर दिया गया था। देश में मेगा फ़ूड पार्क (एमएफपी) योजना के अंतर्गत मंज़ूर 41 परियोजनाओं में से, पिछले तीन सालों में 2 परियोजना परिचालित हो गई हैं, जिससे परिचालित मेगा फ़ूड पार्कों की कुल संख्या 25 हो गई है। इसी तरह, देश में कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर (एपीसी) योजना के अंतर्गत मंज़ूर 63 परियोजनाओं में से, पिछले तीन वर्षों में 6 परियोजनाओं परिचालित हो गई हैं, जिससे परिचालित एपीसी परियोजनाओं की कुल संख्या 23 हो गई है। बिहार राज्य में मंत्रालय द्वारा मंज़ूर एमएफपी और एपीसी परियोजनाओं की जानकारी **अनुबंध** में दी गई है। बिहार राज्य में मंज़ूर तीनों परियोजनाओं पर काम चल रहा है।

(ख): बिहार राज्य में मंत्रालय द्वारा मंज़ूर किए गए दो मेगा फ़ूड पार्क (एमएफपी) परियोजनाओं में उद्यमियों को खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां लगाने के लिए 31 प्लॉट दिए गए हैं, जिनमें से दो इकाइयों ने पिछले तीन वर्षों में उत्पादन शुरू कर दिया है।

(ग) से (ङ): एमफपी के काम, स्वामित्व और प्रबंधन की ज़िम्मेदारी स्पेशल पर्पस व्हीकल (एसवीपी) / कार्यान्वन एजेंसी (आईए) की होती है, जिसे एमएफपी स्थापित करने के मकसद से बनाया गया है। मंत्रालय कार्यक्रम प्रबंधन एजेंसियों (पीएमए) के माध्यम से परियोजनाओं की नियमित निगरानी कर रही है और परियोजनाओं को जल्दी लागू करने के लिए वरिष्ठअधिकारियों और माननीय मंत्री, एफ़पीआई के स्तर पर समीक्षा बैठके करके परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा कर रहा है। मेगा फ़ूड पार्क और कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर का विकास और उपयोग, अंदरूनी सड़कों, कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउसिंग, अपशिष्ट उपचार सुविधाएं और सामान्य प्रसंस्करण सुविधा जैसे सामान्य अवसंरचना के समय पर निर्माण पर निर्भर करता है। एमएफपी और एपीसी द्वारा कार्यान्वन में देरी मुख्य रूप से ज़मीन अधिग्रहण के मुद्दों, कानूनी मंज़ूरी मिलने में देरी, स्पेशल पर्पस व्हीकल (एसवीपी) के पास पैसे की कमी, परियोजना के दायरे में बदलाव, कोविड-19 महामारी जैसे बाहरी कारणों और ज़रूरी संख्या में खाद्य प्रसंस्करण यूनिट को चालू करने में चुनौतियों, जैसे कारणों से होती है।

हालांकि, सरकार ने बिहार समेत कम इस्तेमाल हो रहे एमएफपी और एपीसी में निजी निवेश लाने और ऑक्यूपेंसी बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं । मंज़ूर एमएफपी और एपीसी को खाद्य प्रसंस्करण यूनिट से भरने के लिए, मंत्रालय की खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता सृजन / विस्तार (सीईएफ़पीपीसी) योजना के अंतर्गत एमएफपी और एपीसी के अंदर खाद्य प्रसंस्करण इकाई लगाने के लिए विशेष अभिरुचि की अभिव्यक्ति(ईओआई)

आमंत्रित की गई हैं और बाद में कुछ प्रतिशत निधि विशेष तौर पर मेगा फ़ूड पार्क (एमएफपी) और कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर (एपीसी) के अंदर खाद्य प्रसंस्करण यूनिट के लिए निर्धारित की गई हैं। इसके अलावा, मेगा फ़ूड पार्क, एपीसी और खाद्य प्रसंस्करण इकाई को सस्ता लोन देने के लिए, नाबार्ड के साथ 2000 करोड़ रुपये का विशेष फ़ंड भी बनाया गया है।

(च): बिहार राज्य में स्वीकृत एमएफपी परियोजनाओं ने 934 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित किए हैं।

******

अनुबंध

दिनांक 13.02.2026 को उत्तर हेतु "बिहार में मेगा फूड पार्क और प्रसंस्करण अवसंरचना" के संबंध में राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 160* के भाग (क) में संदर्भित अनुबंध

मंत्रालय द्वारा बिहार राज्य में स्वीकृत मेगा फूड पार्क परियोजनाओं का विवरण:

क्रमांक	एसपीवी/आईए नाम	ज़िला	परियोजना लागत (करोड़ रुपये में)	स्वीकृत अनुदान (करोड़ रुपये में)	जारी अनुदान (करोड़ रुपये में)	स्थिति
1	बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (बीआईएडीए)	मुजफ्फरपुर	180.57	45.4	12.25	कार्यान्वयनाधीन
2	प्रिस्टीन मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड	खगरिया	120.13	41.9	34.8	कार्यान्वयनाधीन

बिहार राज्य में मंत्रालय द्वारा मंज़ूर एपीसी परियोजना का विवरण:

क्रमांक	एसपीवी/आईए नाम	ज़िला	परियोजना लागत (करोड़ रुपये में)	स्वीकृत अनुदान (करोड़ रुपये में)	जारी अनुदान (करोड़ रुपये में)	स्थिति
1	मेसर्स श्रीकंगन फूड पार्क	बेगूसराय	30.43	7.90	2.49	कार्यान्वयनाधीन